जिसके पास
अच्छे दोस्त है
उसे दर्पण की
जरूरत नहीं है।
– अज्ञात

विचार-प्रवाह देहरादून रविवार 9 फरवरी 2020

पेज थ्री
www.page3news.in

राम मंदिर ट्रस्ट के गठन को मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राम मंदिर ट्रस्ट के गठन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में यह जानकारी देते हुए बताया कि ट्रस्ट का नाम 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' रखा गया है।

तारा शर्मा।

अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राम मंदिर ट्रस्ट के गठन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में यह जानकारी देते हुए बताया कि ट्रस्ट का नाम 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' रखा गया है। विवादमुक्त हुई जगह समेत अयोध्या में सरकार द्वारा अधिगृहीत 67 एकड़ जमीन इस ट्रस्ट को दे दी जाएगी।
1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद जब विवाद बढ़ा तो 1993 में अयोध्या में विवादित स्थल सहित आसपास की करीब 67 एकड़ जमीन का केंद्र सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था, तभी से यह जमीन केंद्र के पास थी। केंद्र द्वारा राम मंदिर ट्रस्ध्ट को मंजूरी दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अयोध्ध्या से करीब 22 कध्मिी दूर रौनाही में सुन्ध्नी वक्ध्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया।

गौरतलब है कि नवंबर में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से दिए अपने ऐतिहासिक फैसले में विवादित जमीन पर रामलला का हक माना और वह जमीन राम मंदिर के लिए दे दी, जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए कहीं और जमीन देने का आदेश दिया।
इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए तीन महीने के अंदर एक ट्रस्ट बनाया जाए। अब सरकार ने कोर्ट के आदेश की तामील कर दी है और मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि कुछ उलझनें अब भी सुलझनी बाकी हैं। सरकार ने ट्रस्ट के सदस्यों का नाम अभी नहीं बताया है लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि उसने सोच–समझकर ही इसमें लोगों को रखा होगा। दरअसल, अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के तत्काल बाद जिस तरह वहां के प्रमुख साधु–संतों में टकराव हुआ, जिस तरीके से कई गुटों ने अपनी–अपनी दावेदारी पेश की और आरोप–प्रत्यारोप का दौर चला, उससे ऐसा लगता है कि मंदिर के साथ अनेक पक्षों की आशाएं जुड़ी हैं और वे ट्रस्ट में अपनी अधिक से अधिक हिस्सेदारी चाहते हैं। देखना यह है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में इन दावेदारियों के बीच कितना संतुलन बन पाया है।

मंदिर निर्माण और बाद में उसके सुचारु संचालन के लिए यह संतुलन बहुत जरूरी है। कुछ उलझनें मुस्लिम पक्ष के साथ भी हैं। फैसले के तुरंत बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड के दो सदस्यों ने कहा था कि मस्जिद के लिए अलग से जगह न ली जाए। आज की तारीख में बोर्ड की क्या पोजिशन है, नहीं मालूम। यह भी नहीं पता कि यूपी सरकार ने मस्जिद के लिए जमीन तय करते वक्त मुस्लिम पक्ष की राय ली या नहीं। अच्छा होगा कि यह जगह वहां मस्जिद बनाने वालों को अपने मनमाफिक लगे। सरकार को इस मामले में हर किसी को विश्वास में लेकर चलना चाहिए ताकि लंबे समय से चले आ रहे एक बड़े विवाद का सुखद अंत हो।

अवसाद

अशोक वोहरा।

धर्म-दर्शन

जब तुमने कुछ पाने का विचार किया होगा तो उसके अपने प्रयास भी शुरू किए होंगे लेकिन हर समय को आने में भी समय लगता है। उस समय हम घबराते है और अपने लक्ष्य तक न पहुच पाने के कारण हम अवसाद की स्थिति में घिर जाते है जिससे नस्ट केवल हमारा ही जीवन होता इस प्रस्थिति से निकलना भी तुमको स्वयं से ही होगा अपने आत्मबल को मजबूत कर अपनी मुसीबतों को के8सी कागज पर लिख देखे की क्या जरूरी है अवसाद में रहना या फिर तुम्हारा लक्ष्य ।ये जब जान लोगे तो फिर तुम्हारा स्वयं का स्वयं से साक्षात्कार होगा यही तुम्हरा पुनजागरण होगा। हम स्वयं को जब तक नही पहचान पाते है तो हमारे भीतर छिपी शक्ति हम नागी जान पाते है कोई भी व्यक्ति प्रतिभा लेकर उतपन्न नही होता है उसको प्रतिभावान इसी धरती पर बनाना होता है।

संपादकीय

अनहोनी की आशंका

नगरिकता कानून को लेकर दिल्ली में जारी प्रदर्शनों पर हमले की घटनाओं ने जहां एक तरफ लोगों में असुरक्षा बढ़ाई है, वहीं किसी अनहोनी की आशंका भी पैदा कर दी है। अभी जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव का माहौल चरम पर है, ये वारदात वाकई चिंताजनक हैं। सबसे पहले गुरुवार को सीएए के विरोध में जामिया मिलिया इस्लामिया से राजघाट तक निकाले जा रहे मार्च पर एक नौजवान ने गोली चलाई, जिससे प्रदर्शन में शामिल एक छात्र घायल हो गया।
इस हमले से पहले उसने एक के बाद एक कई फेसबुक पोस्ट जारी किए थे, जो बताते थे कि वह शाहीन बाग में चल रहे सीएए विरोधी धरने से चिढ़ा हुआ है। उसके बाद शनिवार को एक शख्स ने शाहीन बाग पहुंचकर फायरिंग की। गनीमत है कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। फिर रविवार देर रात करीब 11.30 बजे जामिया के गेट नंबर 7 पर धरने पर बैठे आंदोलनकारियों में उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब गेट नंबर पांच पर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। पुलिस ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन जामिया कोऑर्डिनेशन कमिटी के मीडिया ग्रुप में गोली चलने का दावा किया गया। इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पिछले कुछ समय से राजनेताओं के अलावा मीडिया के एक हिस्से ने भी लगातार बयानबाजी की है, जिससे आम लोगों में उत्तेजना पैदा हुई है और अराजक तत्वों का हौसला बढ़ा है।
ऐसी धारणा बनाने की कोशिश की गई है कि सीएए के खिलाध्फ प्रदर्शन कर रहे लोग देश विरोधी हैं। डर इस बात का है कि अगले तीन–चार दिनों में मामले को और बढ़ाकर किसी फ्लैश पॉइंट तक न पहुंचा दिया जाए। जाहिर है, शाहीन बाग की स्थिति बहुत संवेदनशील है।

नागरिकों में सैनिकों के प्रति सम्मान और संवेदना बढ़ाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। सेना में शीर्ष स्तर से ढांचागत सुधारों की शुरुआत कर दी गई है।

दुर्गम इलाकों में तैनात जवान

सुभाष खरे।

यह वाकई चिंता की बात है कि सियाचिन जैसे दुर्गम इलाकों में तैनात जवानों को खाना–कपड़ा और अन्य जरूरी वस्तुएं समय पर नहीं मिल पा रही हैं। नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सीएजी) ने सोमवार को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सियाचिन, लद्दाख और डोकलाम जैसी ऊंची बर्फीली जगहों पर तैनात जवानों को पिछले पांच वर्षों में जरूरी उपकरणों के साथ–साथ राशन की भी किल्लत झेलनी पड़ी है।

रिपोर्ट के अनुसार हाई आल्टिट्यूड इलाकों में पहने जाने वाले विशेष कपड़ों और वहां इस्तेमाल होने वाले जरूरी उपकरणों की खरीद में चार साल तक की देरी हुई, जिसके चलते इनकी काफी कमी हो गई। बर्फीले इलाकों में खतरनाक चौंध से आंखों को बचाने वाले स्नो गॉगल्स की 62 फीसदी तक कमी रही। जवानों को 'मल्टी परपज बूट' नहीं मिल सके जिसके कारण करीब एक साल तक उन्हें पुराने जूतों की मरम्मत करके काम चलाना पड़ा।

खरीद प्रक्रिया में देरी की वजह से सैनिकों की सुरक्षा और साफ–सफाई पर बुरा असर पड़ा। और तो और, खाना भी उन्हें कम कैलोरी का मिला। रिसर्च और डिवेलपमेंट की कमी और स्वदेशीकरण में विफलता के चलते चीजों के

आयात की मजबूरी बनी रही। एक सैन्य अधिकारी की सफाई है कि सीएजी की रिपोर्ट साल 2015–16 से 2018–19 के बीच की है और अब चीजों को सुधार लिया गया है। ये वाकई कितनी सुधरी हैं, इसका पता शायद अगली सीएजी रिपोर्ट में चले, लेकिन अभी तो रिपोर्ट यही बताती है कि दुर्गम जगहों पर तैनात हमारे सैनिक अच्छी स्थितियों में नहीं रह रहे।
इंसानी रिहाइश के लिहाज से संसार की इन सबसे बुरी जगहों में उन्हें हर वक्त चाक–चौबंद रहते हुए दिन में दो बार गश्त लगानी पड़ती है। मौजूदा सरकार ने अपने अजेंडे में राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे ऊपर रख छोड़ा है। नागरिकों में सैनिकों के प्रति सम्मान और संवेदना बढ़ाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। सेना में शीर्ष स्तर से ढांचागत सुधारों की शुरुआत कर दी गई है। संगठन और कामकाज की विसंगतियां दूर की जा रही हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की गई है।

इन बदलावों के अंतिम लाभार्थी हमारे सैनिक ही होने चाहिए। संसार की किसी भी सेना को खाने–पहनने और आत्मरक्षा की जो आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध हैं, वे इन जगहों पर तैनात हमारे सैनिकों को मिलनी चाहिए। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि हमारे सिस्टम की बुनियादी बीमारियों के वे भी उतने ही शिकार हैं, जितना कोई आम आदमी। यह ऐसी बात नहीं जिसे इस कान से सुनकर उस कान से निकाल दिया जाए। अभी बीस साल पहले करगिल में हम देख चुके हैं कि दुर्गम सीमा क्षेत्रों में जरा भी ढीलापन देश के लिए कितना महंगा साबित होता है। हर बार अगर हम कोई भयानक घटना घट जाने के बाद ही चेतेंगे तो फिर राष्ट्रप्रेम को लेकर इतनी लंबी–चौड़ी छोड़ने का मतलब क्या रह जाएगा?

सूडोकू नवताल-5249

मध्यम

8		4	3	9	7	5		6
3					2			
		7	6	5				4
9	6		5			1		7
5		1	4		9	8		2
4		8					5	3
2				6	1	4		
			7					8
7		9	8	3	5	6		1

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकू नवताल -5248 का हल

7	8	4	9	5	2	6	1	3
9	6	2	4	3	1	8	5	7
1	3	5	7	8	6	2	4	9
4	2	3	6	1	5	9	7	8
8	5	9	2	4	7	1	3	6
6	7	1	3	9	8	4	2	5
3	1	7	8	6	4	5	9	2
5	9	6	1	2	3	7	8	4
2	4	8	5	7	9	3	6	1

अपना ब्लॉग

मौसम का मिजाज

मोहन। कार्बन डाई ऑक्साइड के बढ़ते स्तर के कारण वातावरण में तापक्रम बढ़ेगा और इसका सीधा असर ग्लेशियरों पर भी पड़ेगा। एक अनुमान है कि वर्ष 2021 तक अगर हालात यही रहे तो दुनिया में ग्लेशियर तीव्रगति से पिघलेंगे और समुद्र तल में तेजी से वृद्धि होगी। अंतरराष्ट्रीय चर्चाओं से बहुत कुछ हासिल नहीं होता। सच तो यह है कि अब हमें अपने ही स्तर पर समस्या को समझकर अपने को बढ़ते प्रदूषण से और बिगड़ती परिस्थितियों से बचाना होगा। यह तभी संभव है जब हम अपनी आदतें बदलें और नई जीवन पद्धति को अपनाने के लिए तैयार रहें। हमें वर्तमान की कई सुख–सुघविधाएं छोड़ने के लिए भी तैयार रहना होगा। आज खाद्य सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। एक अध्ययन के अनुसार यह पाया गया है कि अगर ऊर्जा की खपत इसी तरह बढ़ती चली गई तो बढ़ते कार्बन डाई ऑक्साइड के कारण दुनिया में 17 करोड़ लोग सीधे खाद्य असुरक्षा के शिकार हो जाएंगे। इनमें भारत के भी लोग होंगे। जलवायु परिवर्तन का भारत पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है।